डाइवर्सिटी

दलित सशक्तिकरण का सर्वोत्तम औज़ार

एच.एल. दुसाध

डाइवर्सिटी

दलित सशक्तिकरण का सर्वोत्तम औजार

एच. एल. दुसाध

डाइवर्सिटी फॉर इक्वालिटी ट्रस्ट
लखनऊ

सातवां संस्करण : अगस्त, 2020
आठवां संस्करण : अगस्त, 2024

प्रकाशक : **डाइवर्सिटी फॉर इक्वालिटी ट्रस्ट**
डाइवर्सिटी हाउस, 2/1467,
आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. : 9654816191

© **डाइवर्सिटी ट्रस्ट**

मूल्य : 800.00 रुपए

रचना	:	**डाइवर्सिटी : दलित सशक्तिकरण का सर्वोत्तम औजार**
लेखक	:	एच.एल. दुसाध
शब्दांकन	:	राकेश पाण्डेय
मुद्रण	:	क्विक ऑफसेट, दिल्ली-94

अब्राहम लिंकन के नवीनतम संस्करण

श्री दिग्विजय सिंह

को

जिन्होंने भारत में डाइवर्सिटी का बीजारोपण कर

दलित सशक्तिकरण की नई राह दिखाई

अनुक्रम

चौथे संस्करण के अवसर पर लेखक का उद्गार! *15*
भूमिका *19*
लेखकीय *25*
शुभेच्छा *40*

ऑस्कर और हम 43
आंग ली ने आस्कर में रचा इतिहास 43; ऑस्कर में भारत का : कारुणिक इतिहास 43; ऑस्कर में भारतीय फिल्मों की विफलता का कारण : मौलिकता का अभाव 44; भारत के सुपर स्टार : नकलची 44; ऑस्कर में विफलता का जिम्मेवार : भारतीय प्रभुवर्ग की मैरिट 45; हॉलीवुड की सफलता का राज 45
ऑस्कर में इतिहास रचने के करीब : लगान 46
लगान : ऑस्कर में नामित होने वाली तीसरी फिल्म 46; सिनेमा के ऋण से मुक्त होने की ज्यादा भावना से समृद्ध : मुसलमान फिल्मकार 46; ऑस्कर में मजबूती से जमने जा रहा है : कालों का झंडा 47
ऑस्कर में अश्वेतों की सफलता का राज 49
ऑस्कर की चर्चा में पहली बार मशगूल : बुद्धिजीवी वर्ग 49; ऑस्कर में विविधता 50; अमेरिका में सबके लिए मुक्त रहा : प्रतियोगिता का अवसर 50; सैग की रिपोर्ट 51; समानांतर ऑस्कर का आंदोलन 52; हॉलीवुड में सामाजिक लोकतंत्र 53; सामाजिक विवेक से शून्य : बॉलीवुड 54;
बॉलीवुड से हॉलीवुड की गुणवत्ता की उम्मीद 55
भगत सिंह वाली फिल्मों को लेकर : बुद्धिजीवी वर्ग में रोष 55; मुम्बइया फिल्मकारों का वैश्य चरित्र 56; भारत में प्रतियोगिता का अवसर सबके लिए नहीं 56; बॉलीवुड की त्रासदी 57; भगतसिंह वाली फिल्मों में नहीं है : व्यावसायिक सफलता की कुंजी 58; व्यावसायिक सफलता की गारंटी हो सकती है : बहुजन नायकों वाली फिल्में 58

बॉलीवुड का दालित्य 60
ऑस्कर में देवदास का दुखद अंत 60; ऑस्कर की भारत को थोड़ी नहीं, बहुत जरूरत है 60; वॉलीवुड के दलितपन का कारण 61; वॉलीवुड की नकलची त्रिमूर्ति 63

सचमुच हॉलीवुड के बिना मर जाएगा बॉलीवुड 65
बालीवुड की औकात 65; हॉलीवुड की कहानियों का स्रोत 66; विश्व की बेहतरीन प्रतिभाओं से समृद्ध हॉलीवुड 67; द्विजों से भरा : बॉलीवुड 67; हॉलीवुड की नकल करने के लिए : क्यों अभिशप्त है बॉलीवुड 68

चैनलों से बाहर दलित 69
चैनलों में दलित आवाज 69; इलेक्ट्रानिक मीडिया में जारी है : घोरतर अस्पृश्यता 70

प्रिंट मीडिया में डाइवर्सिटी की संभावना 72
प्रिंट मीडिया में मुश्किल लग रहा है : विदेशी का प्रवेश 72; प्रिंट मिडिया में एफडीआई लागू करने से : क्यों भाग रही है सरकार 73; मीडिया में एफडीआई से : खुल सकता है डाइवर्सिटी का रास्ता 74

भोपाल घोषणा का नेपथ्य 75
दलित डायरी में डाइवर्सिटी 75; एक नये अमेरिका का दर्शन 76; तिलक बनाम चन्द्रभान प्रसाद 77

भोपाल घोषणा से प्रेरित संविधान समीक्षा समिति 79
निराधार साबित हुई : संविधान समीक्षा आयोग को लेकर आशंका 79; निजीक्षेत्र में आरक्षण का सुझाव 79; काश! संविधन समीक्षा आयोग : भोपाल घोषणा से प्रेरणा लेता 81

भोपाल घोषणा से प्रेरित नई दिल्ली घोषणापत्र 82
क्या दलित आंदोलन सचमुच दिशाहीन है 82; दलितों को वर्तमान दुरावस्था में उबारने में सक्षम : भोपाल घोषणापत्र 82; सप्लाई डाइवर्सिटी लागू करने की दिशा में बढ़ रही हैं सरकारें 83; भोपाल घोषणा से प्रेरित : दिल्ली घोषणापत्र 84; चर्च की गतिविधियों में डाइवर्सिटी की मांग 85

भोपाल घोषणा से प्रेरित बंगलोर पहल 88
बंगलोर में उठी डाइवर्सिटी की मांग 88; डाइवर्सिटी के अभिनव विचार से चमत्कृतः डॉ. यू. आर. अनंतमूर्ति 88

भोपाल घोषणापत्र बनाम महू संकल्प पत्र 91
उमा भारती ने जलाया : भोपाल घोषणापत्र 91; भोपाल घोषणा बनाम महू संकल्प पत्र 91; डाइवर्सिटी : दलित मुक्ति का मैग्नाकार्टा 93; उमा भारती याद करें : संघ का दलित विरोधी काम! 94

शुरू हुई सप्लायर डाइवर्सिटी 95
दिग्विजय सिंह ने कर दिखाया 95; अमेरिका के डाइवसिर्टी सिद्धान्त का भारतीयकरण है : मध्य प्रदेश में लागू सप्लाई डाइवर्सिटी 95; दिग्विजय सिंह की प्रतिश्रुति 96
डाइवर्सिटी से बनेंगे अब दलित करोड़पति 98
मेहनत कर अब बन सकती हूं करोड़पति : दलित उद्यमी उमा सिंह 98; अमेरिकी दलितों को मिला सप्लाई का अवसर 99; सप्लाई डाइवर्सिटी से आया : अश्वेत फर्मों के मुनाफे में उछाल 100; दिग्विजय सिंह की पहल कदमी से : दलित बन सकते हैं करोड़पति 100
लोकतंत्र की सलामती के लिए : डाइवर्सिटी 102
जाति का मीठा 102; प्रभु वर्ग के समक्ष चुनौती है : जाति चेतना का राजनीतिकरण 102; वितरणहीनता के शिकार : दलित 103' अंग्रेजों ने किया : वितरणहीनता से निजात दिलाने की पहल 104; दलितों के वितरणहीनता से निजात दिलाने के लिए : कांशीराम की स्ट्रेटजी 105; जाति चेतना से निजात पाने के लिए : भोपाल घोषणापत्र 105
अस्पृश्यता का प्रतिकार के लिए : डाइवर्सिटी 107
हिन्दुत्व में आस्था के कारण : अस्वीकृत है दलितों की मानवीय सत्ता 108; व्यर्थ का काम है : हिन्दुओं के विवेक को झकझोरना 108; हिन्दुओं की मनोवैज्ञानिक कमजोरी! 109; अस्पृश्यता मोचन में प्रभावी हो सकती है : डाइवर्सिटी 109
दलित उत्पीड़न से निजात के लिए : डाइवर्सिटी 111
दलित दूल्हे का घोड़ी पर चढ़ना : फिर हुआ हिन्दुओं के लिए असहनीय 111; फिर सामने आया : हिन्दुओं का पूर्वाग्रही व असहिष्णु रूप 111; क्यों व्यर्थ होता है हिन्दुओं के विवेक को झकझोरने का अभियान! 113; दलित उत्पीड़न के मूल में हिन्दू धर्म-शास्त्र 113; अत्याचारी वर्ग के जुल्मों से निजात दिलाने का : डॉ. आंबेडकर का नुस्खा 114, दलितों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए : डाइवर्सिटी 115
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से निजात के लिए : डाइवर्सिटी 117
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खौफ! 117; सामाजिक-ऐतिहासिक कारणों से मुक्त बाजार में विफल होने के लिए अभिशप्त है : भारतीय उद्यमी 118; अर्थशास्त्र का शिशु उद्योग तर्क 119; डाइवर्सिटी की शर्त : विदेशी कंपनियों को देश छोड़ने के लिए कर सकती है मजबूर 121
डाइवर्सिटी के बिना मुश्किल है दलित मैडोनाओं का उदय 122
वर्ण-व्यवस्था के अर्थशास्त्र से अनजान : अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला 122;

अपरिवर्तनशील भारतीय समाज 122; दलितों को अंबानी बनाने का सूत्र : सिर्फ भोपाल घोषणा में 123; क्या मैडोना बनने का सपना देखना दलितों के लिए मुमकिन है! 124; हॉलीवुड में मुक्त है : प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर 124; हॉलीवुड की डाइवर्सिटी नीति का कमाल 125

डाइवर्सिटी के रास्ते ही दलित बन सकते हैं अंबानी 126

अंबानी बनने की महत्वाकांक्षा पैदा होने में : कहां है बाधा! 126; वंशानुक्रम का निर्धारित आर्बिट 127; शुद्रातिशूद्रों को अपने आर्बिट से छलांग लगाने का अवसर दिया : आरक्षण 128; दलित अधिकारी—प्रोफेसर तो बने : बन न सके उद्योगपति-व्यापारी 128; अंबानी बनने की महत्वाकांक्षा पैदा कर सकता है : सिर्फ भोपाल घोषणापत्र 129

दलित मुक्ति का सर्वोत्तम मॉडल अमेरिकी डाइवर्सिटी 131

दलितों के आर्थिक विकास से निर्लिप्त : सवर्ण साहित्यकार 131; दलितों के आर्थिक उत्थान के लिए : डोगरा मॉडल 132; अमेरिका और भारत के प्रभुवर्ग में बुनियादी फर्क 133

दलित-मुक्ति के लिए धर्मान्तरण नहीं, डाइवर्सिटी की प्राथमिकता 134

वर्ण-व्यवस्था : एक वितरण व्यवस्था 134; दलित आंदोलन का लक्ष्य : वितरण-शून्यता से निजात दिलाना 136; वितरणहीनता से मुक्ति के लिए : भोपाल घोषणापत्र 137; धर्मान्तरण से पहले : डाइवर्सिटी 138

धर्मार्थ सेवा नहीं : डाइवर्सिटी लागू करने की जरूरत 140

उद्योगपतियों के समक्ष धर्मार्थ सेवा की अपील 140; स्वाधीन भारत में औद्योगिक नीति 141; वैश्यों का परम्परागत चरित्र 142; जरूरत धर्मार्थ सेवा के अपील की नहीं : डाइवर्सिटी लागू करने के लिए दबाव बनाने की है 143

सर्वत्र हिस्सेदारी की मांग क्या दलित आंदोलन से भटकाव है? 144

दलित आंदोलन का दायरा 144; प्रगतिशील सवर्ण भोपाल घोषणा की क्यों नहीं करते चर्चा? 145; वर्ण-व्यवस्था के अर्थशास्त्र के काट के लिए डाइवर्सिटी 146; भागीदारी आंदोलनकारियों की प्राथमिकता 146

अब लागू हो भागेदारी 148

शराब सिंडिकेट का एकाधिकार 148; शराब के दूकानों के आंवटन में बसपा का भागीदारी दर्शन : आर्थिक मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम 149; बसपा का अनवरत भागीदारी अभियान 150; व्यापार-व्यवसाय की दिशा में ठोस प्रगति नहीं : कांशीराम 150; व्यवसाय-वाणिज्य में भागीदारी के लिए : बसपा लाये प्रस्ताव 151

भोपाल घोषणा के खिलाफ भाजपा की रणनीति 152

उमा भारती के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प प्रत्याशित 152; डाइवर्सिटी विरोधी

मुहिम के मोर्चे पर : उमा भारती 156
डॉ. आंबेडकर की दृष्टि में सामाजिक विवेक 157
भारतीयों के सपनों का देश : अमरीका 157; डॉ. अंबेडकर को अमेरिका में मिला : जाति-मुक्त उत्साहवर्द्धक परिवेश 158; ज्ञान के भुक्खड़ : डॉ. आंबेडकर 158; दलितों को नहीं, सुधारने की जरूरत हिंदुओं को है 159; हिन्दुओं की स्थिति आइरिश कुत्ते जैसी 160; अमेरिकी बनाम हिन्दू प्रभुवर्ग 161; अमेरिकी प्रभुवर्ग के सामाजिक विवेक से आया : अश्वेतों के जीवन में सुखद बदलाव 161
सामाजिक विवेक से शून्य : शिक्षक 163
दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों में आरक्षण विरोध की परंपरा 163; उच्च शिक्षा में शिक्षक पदों पर : आरक्षित वर्गों की शोचनीय स्थिति 164; सवर्ण शिक्षकों की सर्वग्रासी आकांक्षा 165; सामाजिक विवेक से शून्य : सवर्ण शिक्षक 165
अनुबंध या दलितों पर प्रतिबंध 167
यूजीसी की प्रस्तावित योजना से स्तब्ध : बौद्धिक जगत 167; संघ के गुप्त एजेंडे से प्रेरित है : यू जी सी की वर्तमान परिकल्पना 168; उच्चशिक्षा में अनुबंध : खत्म कर देगी बहुजन गुरुजनों का अवसर 169; काश! यू जी सी अमेरिका के आकु से प्रेरणा लेती 170; अमेरिका की उच्च शिक्षा में : डाइवर्सिटी का बोलबाला 171; उच्च शिक्षा की बहाली के लिए जिम्मेवार : सवर्ण 172
सामाजिक लोकतंत्र से दूर सवर्ण लेखक 173
अपनी जिम्मेवारियों भागते : सवर्ण लेखक 173; मानवीय अधिकारों के हरण पर विकसित : भारत का जाति समाज 175; अपनी निम्नतर स्थिति से निर्लिप्त : सवर्ण 176; सवर्णों की आत्मकथा में क्यों नहीं उभरता : भारतीय समाज का कूत्सित चित्र 177; बच्चन की आत्मकथा में क्यों विलुप्त है : शूद्रत्व का दंश 178; कितना युक्तिसंगत है दलित साहित्यकारों की यह घोषणा दलित साहित्य सिर्फ दलित ही रच सकते हैं!... 178; अमेरिकी प्रभुवर्ग समाज में कैसे पैदा हो गई : अश्वेत मुक्ति कामी हैरियट स्टो 179; सवर्णों में कोई क्यों नहीं अवतरित हो सका : हैरियत स्टो के रूप में 180; रचना में वैविध्य लाने के लिए : सवर्णों ने किया दलित जीवन का चित्रण 181; हिन्दू विवेक को झकझोरने का सवर्ण साहित्यकारों का अभियान : क्यों हुआ व्यर्थ! 182; हिन्दू ईश्वर-धर्मशास्त्रों के प्रति दुर्बलता पोषण करते रहेः सवर्ण साहित्यकार 184; प्रेमचंद की सोजेवतन : विज्ञान व मानवता विरोधी रचना 185; दलितों की दुर्दशा का मूल कारण : वर्ण-व्यवस्था का अर्थशास्त्र 186; वर्ण-व्यवस्था के अर्थशास्त्र से निर्लिप्त : सवर्ण साहित्यकार 187
हिन्दू पत्रकारिता का सरोकार 189
दलितों के उत्थानमूलक मुद्दों की अनदेखी करती : हिन्दू पत्रकारिता 189; जन्तर

मन्तर पर डाइवर्सिटी मार्च 1899 हिन्दी के अखबारों में : डाइवर्सिटी मांगपत्र की अनदेखी 191; हिन्दी पत्रकारिता की दलित विषयक भूमिका की होनी चाहिए जांच 191; क्या हिन्दी पत्रकारिता : हिन्दू पत्रकारिता है! 192; हिन्दी पत्रकारिता का एक ही इलाज : मीडिया में डाइवर्सिटी 193

मीडिया में डाईवर्सिटी की उपेक्षा 194

सिर्फ हिन्दी पट्टी ही नहीं समग्र भारतवर्ष की पत्रकारिता में होती है : हिन्दू मानसिकता की अभिव्यक्ति 194; समग्र वर्ग की चेतना की दरिद्रता : हिन्दू समाज की क्रूर सच्चाई 195; हिन्दू लेखकों के विश्व मानस का क्षितिज : निहायत ही संकुचित 196; भारतीय पत्रकारिता में डाइवर्सिटी की उपेक्षा 196; मीडिया में बहुजन नायकों की घोरतर उपेक्षा 197; यदि कांशीराम न होते 199

खेलों में आरक्षण खेल नहीं 200

खेलों में आरक्षण की पहलकदमी का : तीव्र विरोध 200; सवर्णों के दिलों में शूल बनकर चुभता है : आरक्षण 200; हिन्दू आरक्षणवादियों की मेरिट! 201; अंबेडकरी आरक्षण का करुण चित्र 202; आरक्षण के विरुद्ध मुस्तैद : भारतीय प्रभुवर्ग का चरित्र 203; हिन्दुओं के दैविक-सिद्धान्तों में आस्था का परिणाम 204; बहुजनों के लिए : खेलों में आरक्षण क्यों है जरूरी 204

आरक्षण के सौ साल 206

आरक्षण शताब्दी वर्ष की गूंज 206; हिन्दू आरक्षण से अनजान : आरक्षण विरोधी 206; आधुनिक आरक्षण का इतिहास 207; हिन्दू-आरक्षण के खिलाफ : आंबेडकर का ऐतिहासिक संघर्ष 208; हिन्दुओं की आरक्षण विरोधी मानसिकता का विस्फोटक रूप 208; आरक्षण समूल नष्ट करने की परिकल्पना 209; आरक्षण के शताब्दी वर्ष में : सामने आई सर्वव्यापी आरक्षण की आइडिया 210; शाहू जी के महाराज के बाद सामने आये एक और राजा : दिग्विजय सिंह 211

वामपंथ का भावान्तरण 212

बसपा की भाषा बोलते : वामपंथी 212; जाति पर विदेशी मार्क्सवादियों के सुझावों की अनदेखी किया : भारतीय मार्क्सवादी 213; वर्ण-व्यवस्था के अर्थशास्त्र का समझें : भारतीय मार्क्सवादी 213; भोपाल घोषणा अपनाना : भारतीय वामपंथ की ऐतिहासिक जरूरत 214

विदेशी निवेश में पूर्व शर्त : डाइवर्सिटी 216

वामदलों द्वारा विदेशी निवेश का : सशर्त अनुमोदन 216; बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति : वामदलों में स्वागतभाव 216; डाइवर्सिटी को अपनी शर्तों में शामिल करें वामपंथी 217

दलित बुद्धिजीवियों की प्राथमिकता 220

भूख की समस्या से निर्लिप्त : दलित बुद्धिजीवी 220; लोकतांत्रिक चरित्र से

शून्य : भारत का प्रभुवर्ग 220; नरसिंह राव की चाणक्य नीति 221; नरसिंह राव को बौना बनाने में जुटे : वाजपेयी 222; अटल की विनिवेश नीति से निर्लिप्त : दलित बुद्धिजीवी 223

विनिवेश हो मगर डाइवर्सिटी की शर्तों पर 225

नहीं थमी रफ्तार पकड़ती : विनिवेश की गाड़ी 225; विनिवेश विरोध के बहाने : देश भक्ति प्रदर्शन में उतरा संघ 226; विनिवेश पर शुरू हुई : देशभक्ति व प्रदर्शन की प्रतियोगिता 227; वाजपेयी ने जाहिर किया : सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का अटल इरादा 228; आरक्षित वर्गों के सफाये से प्रेरित : अटल की विनिवेश नीति 229; मंडल के बाद आरक्षण हुआ : सवर्णों के लिए असनीय 230; किसी ने नहीं सोचा था कि राष्ट्रवादी संघ अपनायेगा : आर्थिक रूप से विदेशियों का गुलाम बनाने वाली अर्थनीति 231; लागू हो : सशर्त विनिवेश नीति 232

विनिवेश पर मौन दलित 233

सामाजिक न्याय के इतिहास का दुखद दिन : 5 अक्तूबर, 2002 233; दलित बुद्धिजीवियों के एजेंडे में नहीं है : आर्थिक मुक्ति का मुद्दा 234; दलित बुद्धिजीवियों की : ऐतिहसिक भूल 234; तय सा दिख रहा हैः लाभजनक सरकारी कंपनियों का विनिवेश 235; डाइवर्सिटी लागू करवाने की लड़ाई लड़ने से : नहीं है श्रेयस्कर उपाय 236

वाजपेयी सरकार का एजेंडा : आरक्षित वर्ग का सफाया 237

विनिवेश विरोध : संघ का नाटक 237; विनिवेश में हो रही है : राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की अनदेखी 239; वाजपेयी के जरिये चल रहा है : संघ का एजेंडा 239; वाजपेयी सरकार का प्रमुख एजेंडा : आरक्षित वर्गों का सफाया 240; विनिवेश हो, मगर डाइवर्सिटी की शर्तों पर 241

दलित डाइवर्सिटी के लिए उग्रवाद का दामन थामें तो? 243

ब्राह्मणों द्वारा आरक्षण के लिए : खून बहाने की धमकी 243; आरक्षण का आधार निर्धनता नहीं : वाजपेयी 243; आरक्षण का आधार क्यों बना सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन 244; हिन्दू आरक्षण में : बाह्मणों का अधिकार 245; हिन्दू ध्रुवीकरण से मिला : सत्ता का लक्ष्य 245

अटलजी, क्या आरक्षण का आधार अब सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं रहेगा? 247

अटल के समक्ष : नया कर्तव्य संकट 247; आरक्षण पर वाजपेयी का स्टैण्ड 247; सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को : आरक्षण का आधार बनाने के पीछे 248; सवर्णों की संपन्नता के पीछे : हिन्दू आरक्षण 249

चुनावी चक्रव्यूह में दलित एजेन्डा 251

नई सदी का पहला लोकसभा चुनाव 251; पार्टियों के घोषणापत्रों में शामिल निजीक्षेत्र में आरक्षण 251; भोपाल का दलित एजेण्डा 252; कांग्रेस का घोषणापत्र बेहतर 253; पूना पैक्ट के जमाने से : संघ रहा है आरक्षण विरोधी 253

फील गुड की काट : बहुजनों की सर्वत्र भागेदारी 254

स्वयंसेवी वाजपेयी ने किया : तीसरी गुलामी का मार्ग प्रशस्त 254; बसपा पर बड़ी जिम्मेवारी 255; संघ का गुप्त एजेंडा : हिन्दू राष्ट्र नहीं, आरक्षण का खात्मा 255; अटल के मंसूबों पर फेरने के लिए : भागीदारी का एजेंडा 256

सामाजिक न्याय की नई पारी की जरूरत 257

सोनिया गांधी पर भाजपा को हराने की : ऐतिहासिक जिम्मेदारी 257; आरक्षण के प्रति : संघ की वितृष्णा 258; तीसरी गुलामी को आमंत्रित करने में : वाजपेयी की तत्परता 259; फील गुड के नशे में चूर : भारत का संभ्रान्त वर्ग 260; फील गुड की सही बात : भोपाल घोषणा 260; सामाजिक न्याय का मुद्दा : साबित हो सकता है संजीवनी 261

हिंदू विवेक पर आश्रित न्यूनतम दलित एजेंडा 262

संप्रग के साझा एजेंडे से : दलित भी आशावादी 262; जाति के पंक में फंसी : हिन्दू मानसिकता 263; समग्र वर्ग की चेतना से शून्य : हिन्दू 263; सोनिया-मनमोहन के प्रयास के प्रति हुआ जा सकता है आशावादी 264

राज्यादेश से ही मिल सकता है निजी क्षेत्र में आरक्षण 265

संप्रग का साझा कार्यक्रम : क्यों बनाता है दलितों को आशावादी 265; कांग्रेस का घोषणापत्र : डाइवर्सिट के प्रति बनाया था आशावादी 266; संप्रग के साभग कर्मसूची में : डाइवर्सिटी की क्यों हुई अनदेखी 267; भारतीय उद्यमियों का दलित विरोधी चरित्र 268

शराब की दूकानों और पार्किंग में डाइवर्सिटी की जरूरत 270

स्तब्धकारी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 270; बड़ी आसानी से गली-गली में खुल सकेंगी : शराब की दुकानें 271; दिल्ली सरकार की पार्किंग नीति 271; आबकारी और पार्किंग नीति को मानवीय चेहरा देने के लिए : लागू हो डाइवर्सिटी 271

सफाई कर्मचारियों पर निजीकरण की गाज 273

निजी हाथों में जा रही है : सफाई व्यवस्था 273; सफाई की प्रस्तावित नीति से : सफाई कर्मचारियों क्षोभ 273; टेक्नालॉजी के सहारे शूद्रातिशूद्रों को किया जा रहा है : परंपरागत पेशों से दूर 274; काश! प्रस्तावित सफाई व्यवस्था में लागू होती : डाइवर्सिटी 275

परिशिष्ट

सामाजिक परिवर्तन और डाइवर्सिटी 276

भारतीय समाज की अपरिवर्तनशीलता 276; इक्कीसवीं सदी में भी अपरिवर्तित : जाति समाज 277; परिवर्तनशील : श्रेणी समाज 277; वर्ण-व्यवस्था : आर्यों के हित में प्रवर्तित एक आरक्षण व्यवस्था 278; सामाजिक-परिवर्तन में बाधक : हिन्दू आरक्षण 279; हिन्दू आरक्षण पर आईपीसी का हमला 280; आधुनिक आरक्षण के प्रवर्तक : फुले 280; आरक्षण से शुरू सामाजिक परिवर्तन 281; आरक्षण के सहारे मूलनिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ना : एक वैश्विक परिघटना 282; दूसरे देशों की तुलना में : भारत के आरक्षण का दायरा छोटा 283; आरक्षण के प्रति ईर्ष्याकातर : शासक वर्ग 283; भारतीय बौद्धिक क्षितिज पर डाइवर्सिटी का उदय 284; भोपाल घोषणा का असर 285; बड़ा आकार लेता डाइवर्सिटी आंदोलन 286; सही दिशा में जा रहे हैं डाइवर्सिटी आंदोलनकारी 287; भूमंडलीकरण के दौर में अप्रासंगिक होती आरक्षण नीति 287; डाइवर्सिटी की जड़ें आंबेडकरवाद में 288

सौ रोगों की एक दवा : डाइवर्सिटी 291

सभ्यताओं का टकराव : धार्मिक व सांस्कृतिक विविधताओं में व्याप्त शत्रुता का परिणाम 291; ग्लोबल वार्मिंग : मानव-जाति के समक्ष नई चुनौती 292; पर्यावरण और संपोषित विकास 293; पर्यावरण की रक्षा के लिए लामबंद हुआ अंतर्राष्ट्रीय जगत 293; जैविक विविधता (Bio-diversity) पर खास चिंता 294; जैविक विविधता के लिए घातक : हिंदू धर्म-संस्कृति 294; भारत में जैव-विविधता का संकट 295; मानव-जाति की सबसे बड़ी समस्या : आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी 296; आर्थिक और सामाजिक विषमता की सृष्टि का कारण : शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का असमान प्रतिबिम्बन 296; समताकामियों द्वारा धार्मिक-शक्ति की उपेक्षा 296; सामाजिक-आर्थिक विषमता के खात्मे के लिए : शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन 297; शक्ति के असमान बंटवारे से पैदा हुआ : क्रांतियों का सैलाब 298; शक्ति-वितरण के लिए : लोकतांत्रिक व्यवस्था 299; विविधता नीति के सहारे विषमता के खात्मे का सर्वोत्तम मिसाल : दक्षिण अफ्रीका 299; भारत में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतीकात्मक प्रदर्शन 300; सामाजिक और लैंगिक विविधता की सबसे बड़ी दुश्मन : वर्ण-व्यवस्था 301; स्वाधीन भारत के सुपर-स्टार नेताः लोकतंत्र-विरोधी 302; बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का उदय 302; डाइवर्सिटी से ही मुमकिन है : धन का न्यायपूर्ण बंटवारा 304; भ्रष्टाचार को कम करने के लिए : डाइवर्सिटी 305; लोकतंत्र की सलामती के लिए :

डाइवर्सिटी 306; मुक्कमल महिला सशक्तीकरण के लिए : डाइवर्सिटी 307; सच्चर रिपोर्ट में उभरी मुस्लिम समुदाय की बदहाली की तस्वीर को खुशहाली में बदलने के लिए : डाइवर्सिटी 307; आरक्षण से उपजते गृहयुद्ध के हालात से निजात पाने के लिए : डाइवर्सिटी 307; नक्सलवाद के शमन के लिए : डाइवर्सिटी 308; अस्पृश्यों को हिन्दुओं के अत्याचार से बचाने के लिए : डाइवर्सिटी 308; बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रोकने के लिए : डाइवर्सिटी 309; विविधता में एकता को सार्थकता प्रदान करने के लिए : डाइवर्सिटी 309; ब्राह्मणशाही के खात्मे के लिए : डाइवर्सिटी 310; सामाजिक प्रदूषण से निर्लिप्त : राजनीतिक पार्टियां 310; पर्यावरणवादियों से प्रेरणा लेने की जरूरत 311

चौथे संस्करण के अवसर पर लेखक का उद्‌गार!

सर्वव्यापी आरक्षण की चाह पैदा करने वाली : बेजोड़ किताब!

इतिहास की विशेष मांग पर इस पुस्तक के सातवें संस्करण का प्रकाशन हो रहा है, जो मेरी पहली पुस्तक 'आदि भारत मुक्ति : बहुजन समाज (मूलनिवासियों के संघर्ष की दास्तान)' के साथ यह पुस्तक मेरे दिन के सबसे करीब है : जिसने लेखन जगत में 'डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया' के रूप में मेरी खास पहचान बनाने के साथ बेशुमार पाठक तैयार किए। डाइवर्सिटी केन्द्रित भारत के इतिहास की इस पहली पुस्तक के प्रकाशन के साथ जिस तेजी से भोपाल सम्मेलन से शुरू हुई डाइवर्सिटी की आइडिया विस्तार पाने लगी, उसमें और तेजी लाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय पासवान के विशेष आग्रह पर 15 मार्च, 2007 को 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन'(बीडीएम) संगठन खड़ा करना पड़ा, जो परवतीकाल में डाइवर्सिटी के वैचारिक आंदोलन को खड़ा करने में महती भूमिका अदा किया। किन परिस्थितियों में बीडीएम वजूद में आया और क्या है इसका एजेंडा व भारतीय समाज व राजनीति पर इसका इम्पैक्ट : इसकी विस्तृत जानकारी परिशिष्ट अध्याय के 'सौ रोगों की एक दवा : डाइवर्सिटी' नामक लेख से मिल सकती है।

परिशिष्ट को एक विशेष मकसद से नए संस्करण में शामिल किया गया है। इसके पूर्व के जो संस्करण छपे थे, उनमें डाइवर्सिटी जैसे नए विषय पर शुरुआती दौर के मेरे विचार थे। इस पर लगातार चिंतन के प्रायः एक दशक बाद मेरी सोच पूरी तरह परिपक्व हुई और उपलब्धि किया कि आर्थिक और सामाजिक विषमता जैसी मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या के साथ अन्यान्य समस्याएँ भी विविधता की अनदेखी का परिणाम हैं, जिसका साक्षात पाठक 'सौ रोगों की एक दवा : डाइवर्सिटी' में करेंगे। परिशिष्ट का पहला लेख आरक्षण के विकास की उस प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए है, जिसके विकास के क्रम में इतिहास ने भारत के जन्मजात वंचितों को सर्वव्यापी आरक्षण वाली डाइवर्सिटी का झण्डा बुलंद करने के से बेहतर कोई विकल्प नहीं छोड़ा।

बहरहाल वैसे तो फरवरी 2005 में इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही पाठकों ने इसके प्रति जिस प्रचंड उत्साह का परिचय दिया,उससे तय हो गया कि भविष्य में इसके

एकाधिक संस्करण प्रकाशित होंगे और ऐसा हुआ भी। डाइवर्सिटी में ही भूमंडलीकरण के सैलाब से बचने की उम्मीद देखते हुये, जिस तरह पाठकों ने इसे हाथो हाथ लिया, उससे 2008 तक देखते ही देखते इसके छह संस्करण प्रकाशित हो गए, फिर भी पाठकों में इसकी मांग बनी रही। किन्तु 2007 के बाद बीडीएम की ओर से हर वर्ष डाइवर्सिटी ईयर बुक सहित डाइवर्सिटी केन्द्रित औसतन पाँच किताबें प्रकाशित होते रहने के कारण, पाठकों के भारी मांग की बावजूद इसका और कोई संस्करण न प्रकाशित न हो सका। किन्तु अब जो हालात पैदा हुये हैं, उसमें इसका एक नया संस्करण लाना इतिहास की जरुरत बन गयी।

2005 में जब इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, मैंने इसकी लेखकीय में कहा था,' निकट भविष्य में आरक्षण महज कागजों की शोभा बनकर रह जाएगा, जिसका परिणाम दो रूपों में सामने आएगा। पहला, देश की कुल जनसंख्या की एक चौथाई मानवेतर आबादी धीरे-धीरे पराधीन भारत वाली स्थिति में पहुँच जाएगी। दूसरा, स्वाधीन भारत में आरक्षण से सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, लगभग पूरी तरह स्तब्ध हो जाएगी।'डेढ़ दशक पूर्व की मेरी वह भविष्यवाणी आज प्रायः पूरी तरह सही साबित हो चुकी है। आज आरक्षण को लगभग पूरी तरह कागजों की शोभा बनाने के साथ जिस तरह संघ प्रशिक्षित प्रधानमंत्री हिन्दू राष्ट्र का सपना पूरा करने के लिए लाभजनक सरकारी कंपनियों के साथ, रेल, बस और हवाई अड्डे, बैंक, हास्पिटल इत्यादि सभी कुछ निजी हाथों में देने मे सर्वशक्ति लगा रहे हैं, उससे सिर्फ दलित–आदिवासी ही नहीं, सम्पूर्ण बहुजन समाज के सामने वैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिन हालातों में भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को कभी अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम छेड़ना पड़ा था। सचमुच आज बहुजनों के समक्ष भारत के काले अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई में कूदने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं बचा है।

आज की तारीख में दुनिया के किसी भी देश में भारत के विशेषाधिकारयुक्त जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग जैसा शक्ति के स्रोतों पर पर औसतन 80-90 प्रतिशत कब्ज़ा नहीं है। आज यदि कोई गौर से देखे तो पता चलेगा कि पूरे देश में जो असंख्य गगनचुम्बी भवन खड़े हैं, उनमें 80-90 प्रतिशत फ्लैट्स इन्हीं के हैं। मेट्रोपोलिटन शहरों से लेकर छोटे-छोटे कस्बों तक में छोटी-बड़ी दुकानों से लेकर बड़े-बड़े शॉपिंग मॉलों में 80-90 प्रतिशत दूकानें इन्हीं की है। चार से आठ-आठ लेन की सड़कों पर चमचमाती गाड़ियों का जो सैलाब नजर आता है, उनमें 90 प्रतिशत से ज्यादे गाड़ियां इन्हीं की होती हैं। देश के जनमत निर्माण में लगे छोटे-बड़े अख़बारों से लेकर तमाम चैनल प्राय इन्ही के हैं। फिल्म और मनोरंजन तथा ज्ञान-उद्योग पर 90 प्रतिशत से ज्यादा कब्ज़ा इन्हीं का है। संसद, विधानसभाओं में वंचित वर्गों के जनप्रतिनिधियों की संख्या भले ही ठीक-ठाक हो, किन्तु मंत्रिमंडलों में दबदबा इन्हीं का है। मंत्रिमंडलों में लिए गए फैसलों को अमलीजामा पहनाने वाले 80-90 प्रतिशत अधिकारी इन्हीं वर्गों से हैं। न्यायिक सेवा,

शासन-प्रशासन, उद्योग-व्यापार, फिल्म-मीडिया, धर्म और ज्ञान क्षेत्र में भारत के जन्मजात सुविधाभोगियों जैसा दबदबा आज की तारीख में दुनिया में कहीं नहीं है। इस दबदबे ने बहुसंख्य लोगों के समक्ष वैसे विकट हालात पैदा कर दिये हैं, जिन हालातों में दुनिया के कई देशों में शासक और गुलाम वर्ग पैदा हुए : ऐसी ही परिस्थितियों में दुनिया के तमाम देशों में स्वाधीनता संग्राम संगठित हुए।

काबिले गौर है कि शासक और गुलाम के बीच मूल पार्थक्य शक्ति के स्रोतों (आर्थिक-राजनीतिक-शैक्षिक-धार्मिक) पर कब्जे में निहित रहता है. गुलाम वे हैं जो शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत रहते हैं, जबकि शासक वे होते हैं, जिनका शक्ति के स्रोतों पर एकाधिकार रहता है। तमाम उपनिवेशों के मूलनिवासियों की दुर्दशा के मूल में शक्ति के स्रोतों पर शासकों का एकाधिकार रहा है। अगर शासकों ने पराधीन बनाये गए लोगों को शक्ति के स्रोतों में वाजिब हिस्सेदारी दिया होता, दुनिया में कहीं भी स्वाधीनता संग्राम संगठित नहीं होता। शक्ति के समस्त स्रोतों पर अंग्रेजों के एकाधिकार रहने के कारण ही भारतवासियों को स्वाधीनता संग्राम का आन्दोलन संगठित करना पड़ा था। आज यदि भारत पर नजर दौड़ाई जाय तो पता चलेगा कि गुलाम भारत में जैसे हालात गुलाम भारतीयों के समक्ष थे, आजाद भारत में आज वही हालात बहुजनों के समक्ष हैं, जिसमें मूलनिवासी बहुजन समाज के समक्ष एक नया स्वाधीनता संग्राम संगठित करने से भिन्न कोई विकल्प ही नहीं बंचा है।

स्मरण रहे दुनिया में जहां- जहां भी गुलामों ने शासकों के खिलाफ मुक्ति की लड़ाई छेड़ी, उसकी शुरुआत आरक्षण से हुयी। काबिलेगौर है कि आरक्षण और कुछ नहीं शक्ति के स्रोतों से जबरन दूर धकेले गए लोगों को शक्ति के स्रोतों में कानूनन हिस्सेदारी दिलाने का माध्यम है। आरक्षण से स्वाधीनता की लड़ाई का सबसे उज्ज्वलतम मिसाल भारत का स्वाधीनता संग्राम है। अंग्रेजी शासन में शक्ति के समस्त स्रोतों पर अंग्रेजों के एकाधिकार दौर में भारत के प्रभुवर्ग के लड़ाई की शुरुआत आरक्षण की विनम्र मांग से हुई। तब उनकी निरंतर विनम्र मांग को देखते हुए अंग्रेजों ने सबसे पहले 1892 में पब्लिक सर्विस कमीशन की द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 941 पदों में 158 पद भारतीयों के लिए आरक्षित किया। एक बार आरक्षण के जरिये शक्ति के स्रोतों का स्वाद चखने के बाद सन 1900 में पीडब्ल्यूडी, रेलवे,टेलीग्राम, चुंगी आदि विभागों के उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं रखे जाने के फैसले की कड़ी निंदा तब के जागरूक भारतियों संस्था कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने तब आज के बहुजनों की भांति निजी कंपनियों में भारतीयों के लिए आरक्षण का आन्दोलन चलाया था। हिन्दुस्तान मिलों के घोषणा पत्रक में कांग्रेस ने उल्लेख किया था कि ऑडिटर, वकील, खरीदने-बेचने वाले दलाल आदि भारतीय ही रखे जाएँ। तब उनकी योग्यता का आधार केवल हिन्दुस्तानी होना था, परीक्षा में कम ज्यादा नंबर लाना नहीं। बहरहाल आरक्षण के जरिये शक्ति के स्रोतों का स्वाद चखते-चखते ही शक्ति के स्रोतों पर सम्पूर्ण एकाधिकार के लिए सवर्णो ने

पूर्ण स्वाधीनता का आन्दोलन छेड़ा और लम्बे समय तक संघर्ष चलाकर अंग्रेजो की जगह खुद काबिज होने में सफल हो गए।

बहरहाल इतिहास की धारा में बहते हुए मूलनिवासी एससी,एसटी, ओबीसी और इनसे धर्मान्तरित तबके के लोग भी आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किन्तु वह लड़ाई शक्ति के समस्त स्रोतों के लिए न होकर : अपने-अपने सेक्टर के आरक्षण बचाने; निजीक्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण बढ़ाने की लड़ाई तक सीमित है। पर, यदि बहुजनों को देश के सुविधाभोगी वर्ग की गुलामी से मुक्ति पानी है, जैसे हिन्दुस्तानियों ने अंग्रेजों से पाया; यदि उन्हें वर्ग संघर्ष में हारी हुई बाजी पलटनी है तो आरक्षण की लड़ाई को मिलिट्री, पुलिस, न्यायपालिका जैसी सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के साथ सप्लाई,डीलरशिप, ठेकेदारी, पार्किंग, परिवहन, ज्ञान उद्योग, फिल्म-मीडिया, पौरोहित्य इत्यादि सहित शक्ति के समस्त स्रोतों तक विस्तार देना होगा। इस सर्वव्यापी आरक्षण को लेकर गाँव गाँव, गली- मोहल्लों तक जाना होगा, जैसे इंडियन लोग अंग्रेजों के खिलाफ किए। जब दलित, आदिवासी, पिछड़े और इनसे धर्मांतरित तबकों में चप्पे-चप्पे में आरक्षण की महत्वाकांक्षा पनपेगी, तब भारत उस दक्षित अफ्रीका जैसा बन जाएगा जहां मूलनिवासी कालों की तानाशाही सत्ता है। इस तानाशाही सत्ता के ज़ोर से वहाँ के काले शासकों ने ऐसी नीतियाँ बनाई है, जिसके कारण वहाँ भारत के सवर्णो की भांति हर क्षेत्र में 80-90 प्रतिशत कब्जा जमाने वाले गोरे अवसरों के इस्तेमाल के मामले में अपने संख्यानुपात 8-9 प्रतिशत पर सिमटने के लिए बाध्य हैं।

स्मरण रहे आज बहुजन शासक दलों की आरक्षण विरोधी साज़िशों के कारण विशुद्ध गुलामों की स्थिति में पहुँच गए हैं। इस गुलामी से मुक्ति का एकमेव उपाय है बहुजनों की तानाशाही सत्ता, जो तभी मिल सकती है जब बहुजनों में पैदा होगी सर्वव्यापी आरक्षण की उत्कट चाह! और जहां तक सर्वव्यापी आरक्षण की उत्कट चाह पैदा करने का सवाल है, भारत में आज तक ऐसी किताब नहीं आई है, जो अभी आपके हाथ में पड़ी किताब का मुक़ाबला कर सके। इसलिए बहुजनों के आजादी की लड़ाई की जरूरत को ध्यान में रखते हुये इसका नया संस्करण प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक बहुजनों के मुक्ति संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका अदा करेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।

अंत में! इस पुस्तक का नया संस्करण लाने में उत्कट विद्वान जयप्रकाश फ़ाकिर, बहुजन भारत की असाधारण लेखिका शैली किरण, डॉ. प्रकाश ठाकुर, डॉ. जनमेजय कुमार ने जो अपार उत्साहवर्द्धन किया है, उसके लिए विशेष आभार प्रकट करता हूँ।

15 अगस्त, 2020

–एच.एल. दुसाध
संस्थापक अध्यक्ष,
बहुजन डाइवर्सिटी मिशन, दिल्ली

भूमिका

यह ऐतिहासिक महत्त्व की किताब है

–चन्द्रभान प्रसाद
[दलित चिंतक व स्तंभकार]

वर्ष 1942 *भारत छोड़ों* आंदोलन के रूप में जाना जाता है। भारतीय इतिहास का यह मील का पत्थर है। ठीक वैसे ही जैसे वर्ष 1857, *भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम*। भारत, भारत है, और दलित, दलित। जो कभी अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए था, वह अंतर्विरोध की अति है। वर्ष 1857 में ब्रिटिश सरकार का प्रथम वह सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें आदेश दिया गया कि, *स्कूलों में एडमिशन के समय, जाति, नस्ल आदि का भेदभाव न किया जाय*। जैसा कि हम जानते हैं, उस समय, स्कूलों में अछूत बच्चों का प्रवेश वर्जित था। दलित शिक्षा के पक्ष में, यह पहला सरकारी आदेश था। पर, क्या भारतवासी, वर्ष 1857 को इस वजह से एक मील का पत्थर मानेंगे?

1942 में डॉ. आंबेडकर ने रखा : ठेकों में आरक्षण की मांग

ठीक उसी तरह, वर्ष 1942 को *भारत छोड़ो* आंदोलन के लिए जाना जाता है। इसी वर्ष, यानि, अक्टूबर 29, 1942 को बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने, तत्कालीन गवर्नर-जनरल को एक ज्ञापन दिया था। तब वे गवर्नर-जनरल की काउंसिल में लेबर मेंबर थे, यानि लेबर मिनिस्टर। इसलिए उनका यह ज्ञापन, गोपनीय था। उक्त ज्ञापन, जिसका शीर्षक हैं अनुसूचित जातियों की शिकायतें (Grievances of the Scheduled castes), तथा जिसमें उन्होंने, दलित समाज की तमाम मुसीबतों का जिक्र किया एवं दलित अधिकारों की मांग की। उन्हीं मांगों में एक मांग थी, केंद्रीय पी.डब्ल्यू.डी. के ठेकों में दलितों की भागेदारी। डॉ. आंबेडकर वांग्मय, पृष्ठ 435-436 ग्रंथ 10 में वह आज भी मौजूद है। अर्थ यह कि, डाइर्सिटी सिद्धान्त

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

✓ We champion diverse voices and perspectives

✓ Your support helps amplify underrepresented authors

✓ We provide free access to educational institutions

✓ Building bridges through shared stories

✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

- Curate diverse book collections
- Support authors from marginalized communities
- Provide free resources to educators
- Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library